



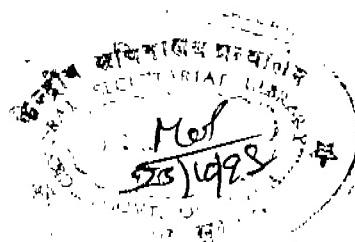
भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 35]
No. 35]

नई दिल्ली, मुधवार, जुलाई 1, 1998/आषाढ़ 10, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1998/ASADHA 10, 1920

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1998

सं. टी. ए. एम. पी. /2/97-एम. पी. टी.—महापत्रन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण प्रशुल्क के नियतन के लिए जलयानों का “तटीय” और “विदेशगामी” के रूप में वर्गीकरण करने के बारे एतद्वारा एक आदेश जारी करता है।

[ए डी वी टी/III/IV/143/98 Exty.]

एस. सत्यम, अध्यक्ष

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. TAMP/2/97-MPT

चेन्नई पत्रन न्यास आवेदक

आदेश

(2 जून, 1998 को पारित)

यह मामला चेन्नई पत्रन न्यास द्वारा दिए गए आवेदन से उत्पन्न हुआ है जिसमें प्रशुल्क प्रयोजनों के लिए “तटीय” अथवा “विदेशगामी” के रूप में जलयानों का विभाजन करने के मानदंडों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

2. चूंकि इस मामले का सभी महापत्रनों के साथ सामान्य सम्बन्ध है, इसलिए इस मुद्रे की नौवहन महानिदेशक के परामर्श से जांच की गई है। नौवहन महानिदेशक ने सिफारिश की है कि तटीय यात्राओं के लिए किसी विदेशगामी जलयान (चाहे वह देशी हो अथवा विदेशी) के परिवर्तन की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की सुविधा से तटीय प्रवालन के लिए अधिक जलयान उपलब्ध होंगे। यदि तटीय जलयानों द्वारा माल की शिपमेंट में संबद्ध लागत अधिक होगी तो तटीय यातायात के लिए जहाज नियोजित करने के लिए शिपर्स कम प्रेरित होंगे। इस तर्क के आधार पर उन्होंने कुछ शर्तों के अध्यधीन सरलता से संपरिवर्तनीयता की सिफारिश की है।

3. नौवहन महानिदेशक के मत को स्वीकार करते हुए और इस संबंध में एक समान नीति के लिए निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण सभी महापत्रों द्वारा सामान्य रूप से अपनाए जाने वाली निम्नलिखित प्रणाली निर्धारित करता है,

- (i) कोई भारतीय ध्वजधारी विदेशगामी जलयान जिसके पास सामान्य ट्रेडिंग लाइसेंस हो, सीमाशुल्क संपरिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय यात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।
- (ii) कोई विदेशी ध्वजधारी विदेशगामी जलयान नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय यात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।
- (iii) ऐसे परिवर्तन के मामले में जलयान में तटीय माल का लदान शुरू होने के समय से लदान पत्तन द्वारा तटीय दर वसूल किए जाएंगे।
- (vi) ऐसे परिवर्तन के मामले में तटीय दर जलयान द्वारा प्रचालन का निष्पादन पूरा किए जाने तक वसूल किए जाएंगे और उसके तुरन्त बाद निष्पादन पत्तन द्वारा विदेशगामी दर वसूल की जाएंगी।
- (v) आवश्यक भारतीय तटीय जलयानों जिनके पास नौवहन महानिदेशक से प्राप्त तटीय लाइसेंस हो, के लिए तटीय दरों के लिए मान्य किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता न होगी।

एस. सत्यम्, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1998

No. TAMP/2/97-MPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby issues an order about classification of vessels as 'coastal' or 'foreign going' for fixation of tariff.

[ADVT/III/IV/143/98 Exty]

S. SATHYAM, Chairman

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/2/97-MPT

The Chennai Port Trust Applicant

ORDER

(Passed on this 2nd day of June, 1998)

This case arises out of an application made by the Chennai Port Trust proposing some modifications in the criteria for distinguishing vessels as 'coastal' or 'foreign going' for tariff purposes.

2. Since this is a matter of common concern to all the major ports, the issue has been examined in consultation with the Director General of Shipping. The Director General of Shipping has recommended that conversion of a foreign going vessel (whether under Indian flag or foreign flag) for coastal runs must be permitted since such a facility will make for a larger availability of ships for coastal operation. If the associated cost in shipment of goods by coastal ships is high, then, shippers will be less motivated to employ ships for coastal traffic. Based on this logic, he has recommended easy convertibility subject, however, to certain conditions.

3. Accepting the opinion of the Director General of Shipping, and bearing in mind the unexceptionable demand for a uniform approach in this regard, this Authority prescribes the following system of classification for common adoption by all the major ports :

- (i) A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order.
- (ii) A foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Coastal Voyage Licence issued by the Director General of Shipping.

- (iii) In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
- (iv) In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable only till the vessel completes discharging operations; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
- (v) For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.

S. SATHYAM, Chairman

